



YouTube LIVE STREAM



वर्ष 13 • अंक: 132

CITY NEWS MUMBAI

दैनिक

सिद्धी न्यूज

सच का जोश

मुंबई

मराठा आरक्षण उपसमिति की अहम बैठक, मुख्यमंत्री ने जारांगे पाटिल को भेजा निमंत्रण पत्र



मुंबई. इस समय राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चा में है. सरकार को दी गई समय सीमा के अंदर कोई फैसला नहीं लेने पर मनोज जारांगे ने मुंबई में आमरण अनशन का ऐलान किया है. जारांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि 20 जनवरी तक आरक्षण पर फैसला ले, नहीं तो हम आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे. वहीं, जारांगे की चेतावनी के बाद मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से आंदोलन में जबरदस्त तेजी आ गई है.

मराठा आरक्षण उपसमिति की अहम बैठक आज होगी. ये बैठक आज शाम 4 बजे होगी. यह बैठक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के

शेष पृष्ठ 7 पर

अजित पवार के बाद शिरूर लोकसभा सीट पर शिंदे गुट का दावा?

सियासी माहौल गरमाने की आशंका

शिरूर लोकसभा सीट पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आपसी दावेदारी के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें जवाब देने शिरूर लोकसभा आ रहे हैं. मुख्यमंत्री का शिव संकल्प अभियान 6 जनवरी को शिरूर लोकसभा से शुरू हो रहा है. चर्चा है कि इसके जरिए वह शिरूर लोकसभा में अपनी ताकत दिखाएंगे. इसलिए शिरूर लोकसभा सीट पर शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच टकराव देखने की आशंका है. वहीं शिवाजीराव पाटिल ने मुख्यमंत्री शिंदे



के दौरे की जानकारी दी है.

कैसे मिलेगी ये सीट? शिरूर लोकसभा सीट पर महागठबंधन में

कैसे लड़ना चाहिए, इसे लेकर दावे-प्रतिदावे चल रहे हैं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि हम

शिरूर लोकसभा सीट लड़ेंगे और जीतेंगे. दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन में शामिल अजित पवार ने आपसी सहमति से यह दावा किया है. अजित पवार के इसी दावे के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस लोकसभा क्षेत्र में रैली कर रहे हैं. इसलिए, उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि शिवाजीराव अदलराव पाटिल शिंदे समूह से उम्मीदवार हैं. क्या बोले पाटिल? इस बारे में बात करते हुए पाटिल ने कहा कि, "अजित पवार के शिरूर लोकसभा उम्मीदवार जो शरद पवार

शेष पृष्ठ 7 पर

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 12 जनवरी को; तीन कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर बड़े फैसले के आसार

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति तीन कांग्रेस सदस्यों को सदन से निलंबित करने के मुद्दे पर विचार करेगी। अगले सप्ताह आहूत बैठक में सांसदों के निलंबन पर अहम फैसला होने की उम्मीद है। भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं। 12 जनवरी को समिति की बैठक में तीन कांग्रेस सांसदों- के जयकुमार, अब्दुल खालिक और विजयकुमार विजय वसंत के बयान दर्ज किए जाएंगे। बीते 18 दिसंबर को संसद में अशोभनीय आचरण के आरोप में तीनों को



स्पीकर ओम बिरला ने निलंबित कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी की बैठक के दौरान 'सदन में गंभीर अव्यवस्था' पैदा करने के आरोपी तीनों कांग्रेस सांसदों को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति

के समक्ष मौखिक साक्ष्य दर्ज कराने होंगे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 100 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए गए सांसद, 13 दिसंबर के दिन संसद की सुरक्षा

में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी से सदन में बयान की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने तख्तियां लेकर सदन में आने और वेल में घुसकर नारेबाजी पर नाराजगी प्रकट की। गतिरोध खत्म न होने पर दो दिनों में कुल 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। स्पीकर की तरफ से लिए गए सख्त एक्शन के मुताबिक 97 सदस्य पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित किए गए, जबकि के जयकुमार, अब्दुल खालिक और विजयकुमार विजय वसंत का

शेष पृष्ठ 7 पर

महिलाओं की सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। तमिलनाडु की यात्रा के बाद पीएम मोदी बुधवार को केरल जाएंगे। केरल कांग्रेस प्रमुख के सुरेंद्रन यात्रा के बारे में बताया कि पीएम मोदी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसी के साथ वे भाजपा-एनडीए के एक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। सुरेंद्रन का दावा-दक्षिणी राज्यों की इतिहास में पहली बार महिलाओं का इतना बड़ा कार्यक्रम सुरेंद्रन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तीन जनवरी को केरल में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। सुरेंद्रन ने बताया कि 'स्त्री शक्ति समागम' कार्यक्रम संसद के दोनों सदन में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई देने के लिए आयोजित किया जा रहा है।



शेष पृष्ठ 7 पर

महाराष्ट्र में किस आधार पर I.N.D.I.A अलायंस में होगा सीटों का बंटवारा? किसे-कितनी सीटें मिलेंगी?

मुंबई: महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा सीटों के लिए I.N.D.I.A अलायंस (महाविकास आघाड़ी) के घटक दलों के बीच भले ही बयानबाजी जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर फैसला इस महीने के अंत तक ही हो पाएगा। मुमकिन है कि कुछ वक्त और लग जाए। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक 48 सीटें हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि इस

राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए/महायुति (महाराष्ट्र में) को कम सीटों पर रोका जाए। शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद वर्तमान में सबसे ज्यादा पेचीदी राजनीति महाराष्ट्र में है। 2024 के चुनावों में जहां एक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा तो वहीं महाराष्ट्र में



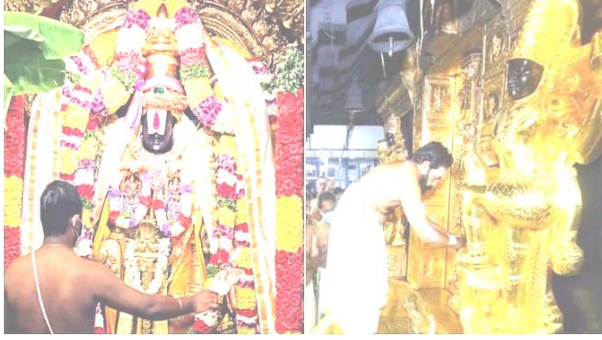
दूसरा मुकाबला शिवसेना और एनसीपी के दोनों खेमों के बीच खुद को आगे रखने के लिए होगा। इन फैक्टर पर तय होगी सीटें? नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में कांग्रेस को 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सीटों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर शिव सेना (उद्धव बाला

साहब ठाकरे) की पार्टी होगी। इसके बाद शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और फिर प्रकाश अंबेडकर को वंचित बहुजन आघाड़ी होगा। प्रकाश अंबेडकर के I.N.D.I.A अलायंस में आने पर दो सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सह-प्रभारी आशीष दुआ के अनुसार सीट शेयरिंग कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। घटक दलों की

शेष पृष्ठ 7 पर

तिरुपति में भक्तों ने दान किए 40 करोड़; सबरीमाला दर्शन के लिए 10 जनवरी से कोई स्पॉट बुकिंग नहीं

भारत में मंदिर से जुड़ी आस्था के कारण श्रद्धालु करोड़ों रुपये का चढ़ावा अर्पित करते हैं। आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर में 10 दिनों के भीतर श्रद्धालुओं ने 40 करोड़ रुपये अर्पित किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे की राशि तिरुपति में श्री वैकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् (TTD) को मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि 23 दिसंबर, 2023 से एक जनवरी, 2024 तक 10-दिवसीय वियाकंटादारा दर्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तों ने 40 करोड़ रुपये दान पेटी में डाले। इसे यहां की भाषा में हंडी का चढ़ावा (hundi collections) कहा जाता है। तिरुपति के अलावा केरल के सबरीमाला से जुड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है। 10 दिन में 6.47 लाख भक्तों ने



दर्शन किया दुनियाभर में प्रसिद्ध तिरुपति का प्रसाद- लड्डू 36 लाख बेचा गया। दो लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को खास अनुष्ठान की सुविधा प्रदान की गई। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने कहा, वैकंटदवारा दर्शन में रिकॉर्ड संख्या में भक्त उमड़े। 10 दिनों में 6.47 लाख भक्तों ने दर्शन किया। इस दौरान भक्तों को लंबी कतारों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। वैकंटदवारा दर्शन के दौरान सामान्य से अधिक भक्तों को

अन्ना प्रसादम (भोजन) भी दिया गया। सबरीमाला में मकरविलक्कु महोत्सव की तैयारियां तिरुपति के अलावा हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन करने केरल के सबरीमाला मंदिर भी जाते हैं। सबरीमाला में मकरविलक्कु महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने एक बयान में कहा कि 10 जनवरी से तीर्थयात्रियों को स्पॉट बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। मंदिर प्रबंधन

की शीर्ष संस्था- TDB ने कहा कि 15 जनवरी को मकरविलक्कु के दिन वर्चुअल कतार में दर्शन के लिए केवल 40,000 बुकिंग ही कराई जा सकेगी। सबरीमाला में तीर्थयात्री 20 जनवरी तक दर्शन कर सकेंगे नए इंतजाम को लेकर टीडीबी के अध्यक्ष पीएस प्रशांत ने कहा कि इन नियमों का मकसद मंदिर परिसर यानी सन्निधम में भारी भीड़ से बचना है। मकरविलक्कु के दिन भक्तों को सुचारू और सुरक्षित दर्शन अनुभव सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं और बाल तीर्थयात्रियों को 14 और 15 जनवरी के दिन भगवान अयप्पा मंदिर में जाने से बचने की सलाह दी गई है। टीडीबी सूत्रों के अनुसार, मकरविलक्कु के बाद सबरीमाला आने वाले तीर्थयात्री 20 जनवरी तक दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।

सरकार-ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह; ड्राइवर्स तुरंत काम पर लौटेंगे, आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म



हित एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के बीच जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, रहमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

नए कानून की धारा के तहत अभी कार्रवाई नहीं होगी अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बातना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर की चिंताओं को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बैठक के बाद ट्रांसपोर्टर क्या बोले? अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की। उन्होंने ड्राइवर्स से कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें। खुद गृह मंत्री शाह से मिला आश्वासन उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।

तमंचे के बल पर दवा कारोबारी के नौकर से 32 हजार लूटे, आरोपी सीसीटीवी में कैद, पुलिस बता रही संदिग्ध

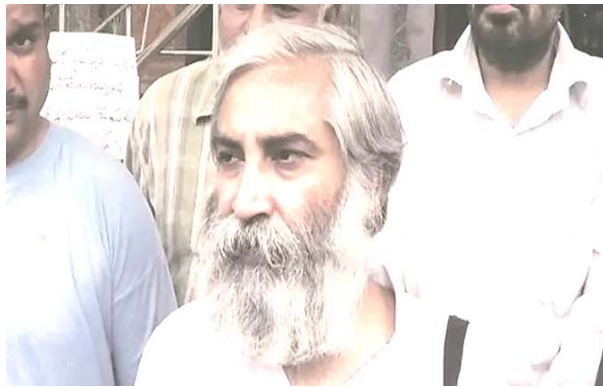


हाथरस में मेडिकल स्टोर के नौकर ने चार बाइक सवार बदमाशों पर तमंचे के बल पर 32 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूटने का आरोप लगाया है। घटना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के ऐंहन और पुरा के बीच की बताई जा रही है। हालांकि आरोपी मोबाइल फोन को घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर फेंककर भाग गए। आरोपी बैंक के सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। श्याम पुत्र दलवीर सिंह निवासी दरकई थाना चंदपा हाथरस जंक्शन क्षेत्र के लाइपुर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। वह दवा की आपूर्ति का काम करता है। उनका आरोप है कि वह 2 जनवरी को ऐंहन के एक मेडिकल स्टोर में दवा देकर लौट रहे थे। रास्ते में चार बाइक सवार बदमाशों ने उनके सामने बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने तमंचे के बल पर उनसे 32 हजार लूट लिए। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट के आरोपी बैंक के सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। श्याम ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। कोतवाली हाथरस जंक्शन के अपराध निरीक्षक के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला कारोबारी विवाद का प्रतीत हो रहा है। श्याम ने बताया कि आरोपियों ने उनके सामने बाइक लगाकर उन्हें रोका। तमंचे के बल पर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने रुपयों के साथ उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। आरोपी रुपये ले गए, लेकिन मोबाइल फोन को करीब 500 मीटर की दूरी पर सरसों के खेत में फेंक कर भाग गए।

कार्यकर्ता संदीप पांडे ने लौटाया मैग्सेसे पुरस्कार, गाजा संघर्ष में अमेरिकी भूमिका की निंदा की

सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने गाजा में इस्त्राइली हमलों में अमेरिका की 'भूमिका' के विरोध में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार उन्हें साल 2002 में दिया गया था। सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से जुड़े पांडे ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से हासिल अपनी दोहरी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी लौटाने का फैसला किया है। मैग्सेसे पुरस्कार ने अमेरिकी फाउंडेशन के साथ जुड़ाव के कारण पांडे की चिंताओं को बढ़ा दिया। एक बयान में उन्होंने फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ चल रहे हमले में इस्त्राइल के लिए अमेरिका के समर्थन पर अपनी असहजता व्यक्त की। मैग्सेसे पुरस्कार मुख्य रूप से रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने कहा, 'युद्ध में फलस्तीनी के 21,500 से अधिक मारे जा चुके हैं और अमेरिका अभी भी इस्त्राइल को

हथियार बेचना जारी रखे हुए है। फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ मौजूदा हमले में इस्त्राइल का खुलकर समर्थन करने में अमेरिका की भूमिका को देखते हुए मेरे लिए पुरस्कार रखना असहनीय हो गया है। इसलिए मैं पुरस्कार लौटाने का फैसला कर रहा हूँ।' मैग्सेसे पुरस्कार के अलावा, संदीप पांडे ने सिरेक्यूज विश्वविद्यालय को विनिर्माण और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी दोहरी एमएससी डिग्री और बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो मानवाधिकारों का सबसे अधिक सम्मान करता है और अभिव्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन, दुख की बात है कि यह केवल देश के भीतर सच है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका



फैसला अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका के 'दोहरे मानदंडों' से उपजा है, विशेष रूप से इस्त्राइल-फलस्तीन संघर्ष पर उसके रुख से। अमेरिकी सरकार के रुख पर निराशा जताते हुए संदीप पांडे ने कहा, 'मुझे कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका दुनिया की लोकप्रिय राय के विपरीत फलस्तीनियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने के लिए इस्त्राइल को प्रोत्साहित करने के लिए

जिम्मेदार है।' पांडे ने फिलिस्तीन के एक संप्रभु राज्य के निर्माण और संघर्ष को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी मान्यता का आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका से अपने पिछले कार्यों के समान मध्यस्थता की भूमिका निभाने का आग्रह किया, और फलस्तीनियों की पीड़ा को दूर करने में अपनी विफलता की आलोचना की।

हड़ताल के बीच पेट्रोल लेने पहुंचा युवक, बहस होने पर पंप मालिक ने मारी गोली



ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से पंजाब में पेट्रोल पंपों पर अफरा-

तफरी मची है। इस बीच फरीदकोट जिले में भी एक शख्स तेल लेने

पेट्रोल पंप पहुंचा। इस दौरान उसकी पंप मालिक से बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गोली लगने से अमरेंद्र सिंह नाम का युवक घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मंगलवार शाम औलख गांव स्थित फरीद किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की है। पुलिस ने जानकारी दी कि

मोटरसाइकिल में तेल भरवाने तीन युवक आए थे। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है। सूचना के बाद कोटकपूरा के डीएसपी शमशेर सिंह शेरगिल और थाना सदर कोटकपूरा के एसएचओ चमकौर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। अन्नामलाई ने बताया कि इस मौके पर डाक विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

चीनी नागरिकों की कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी; मोबाइल एप्स से लोन मामले में तेज हुई कार्रवाई

मोबाइल फोन के जरिए पैसा उधार देने वाली चीनी कंपनियों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। ईडी चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच कर रही है। ताजा घटनाक्रम में दो कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने नए सिरे से तलाशी ली। रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारियों ने मोबाइल एप की जांच के साथ-साथ उधार लेने वाले लोगों के निजी विवरण भी खंगाले।

पिछले साल 19 ठिकानों पर ली गई थी तलाशी मंगलवार को ईडी ने एक बयान में कहा, पिछले साल 21 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में 19 ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। शाइनवे टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसटीआईपीएल), एमपर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड



(एमएसपीएल) समेत कई अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी छापेमारी और तलाशी ली गई थी। ईडी ने कहा, फिनटेक कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाले मोबाइल एप कम समय के लिए लोन का ऑफर देकर ग्राहकों को फंसा रहे थे। ऑनलाइन लेन-देन के इन मामलों में लोन लेने वाले लोगों से अत्यधिक ब्याज वसूलने की बात भी सामने आई। भ्रामक और अनैतिक गतिविधियों से ग्राहकों को परेशान किया जा रहा था।

लोन देने के बाद ग्राहकों को धमकी भी देते थे उधार लेने वाले लोगों के फोन में सहेजी गई तस्वीरों जैसी निजी जानकारीयों तक भी चीनी संस्थाओं का एक्सेस था। फोटो गैलरी और फोन नंबर गैरकानूनी तरीके से हासिल करने के बाद ग्राहकों को धमकी दी जा रही थी। पैसे उधार देने वाले लोग शोषण करने के लिए डेटा लीक करने की धमकी देते थे। तस्वीरों को संपादित कर बदनाम करने और फर्जी कानूनी नोटिस भेजने जैसे गंभीर मामले भी सामने

आए। ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों ने चीनी व्यक्तियों और कंपनियों की तरफ से भारत में 'डमी' निदेशक और ग्राहक बनाए हैं। गलत तरीकों से इनका कारोबार बढ़ रहा है। चीनी नागरिकों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कंपनी सेक्रेटरी और सलाहकार जैसे पेशेवरों की मदद से भारत में फिनटेक कंपनियों खड़ी कीं। एनबीएफसी का जटिल जाल भी बुना गया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक (बेंगलुरु पुलिस) और तेलंगाना (काजीपेट और जनगांव पुलिस) में दर्ज एफआईआर के बाद सुविधियों में आया। ईडी के मुताबिक इन राज्यों में तलाशी के दौरान 1.30 करोड़ रुपये नकद और 'आपत्तिजनक' दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। पिछले साल जून में लगभग 6-7 ठिकानों पर तलाशी के बाद 19.43 करोड़ रुपये के बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त किए गए थे।

आरएमएल अस्पताल में निःशुल्क कंबल वितरण बैंक का उद्घाटन, 'आओ साथ चलें' संस्था ने की पहल



मरीजों का इलाज कराने आए तीमारदारों को दिल्ली की भीषण ठंड से बचाने के लिए मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख और दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने आरएमएल अस्पताल में निःशुल्क कंबल वितरण बैंक का उद्घाटन किया। इस मौके पर संजय मयूख ने सैकड़ों तीमारदारों को कंबल वितरित किए। 'आओ साथ चलें' संस्था द्वारा निःशुल्क कंबल बैंक कई वर्षों से संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में संजय मयूख, विष्णु मित्तल के अलावा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संजय मयूख ने कहा कि अस्पताल में बहुत दूर-दूर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। उनको ठंड से सुरक्षित रखने के लिए कंबल बैंक जैसी पहल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जिन लोगों को जरूरत है, उनकी मदद के लिए समर्थ लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विष्णु मित्तल की अगुवाई में जिस तरह से मरीजों के सहायकों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण, कंबल उपलब्ध कराने और इलाज में मदद जैसे सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल और आओ साथ चलें संस्था के राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए संस्था कई सेवा प्रकल्प चला रही हैं। ठंड में कंबल बैंक उनमें से एक है। इसके अलावा प्रसादम और वस्त्रम जैसे अभियान भी प्रमुखता से चलाए जा रहे हैं। आओ साथ चलें संस्था द्वारा ठंड में कंबल बैंक बीते कई वर्षों से चलाया जा रहा है। आरएमएल में मरीजों का इलाज कराने आए लोगों को आओ साथ चलें संस्था द्वारा टोकन के माध्यम से बिना किसी पैसे के कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे ठंड में अपना बचाव कर सकें। हर साल बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता के कंबलों का इंतजाम किया जाता है।

भाजपा का निमंत्रण नहीं चाहिए, अयोध्या में भगवान का कार्यक्रम है, वे बुलाएंगे तो जाऊंगा



अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे श्रीराम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भाजपा और सपा में जुबानी जंग तीखी हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि अयोध्या में भगवान राम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भगवान से बड़े नहीं हो सकते। भगवान जिसे बुलाएंगे, वही अयोध्या जा सकेगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान कब किसे बुला लें, कोई नहीं जानता। सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम पर

अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर ये तंज कसे। सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान के कार्यक्रम में भाजपा तय कर रही है कि मेहमान कौन होगा। कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। बाकायदा सूची बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के निमंत्रण का इंतजार नहीं रहे हैं। अगर भगवान बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। समाजवादी महिला सभा के कार्यक्रम में भी अखिलेश ने इसी तरह का बयान दिया था। इससे पहले

प्रदेश मुख्यालय पर सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने मंगलवार को नव वर्ष पर गीत और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने कलाकारों को प्रोत्साहित किया और देर तक उनके गीत सुने। पूर्व सांसद एवं हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कवि एवं लेखक क्रांति का संदेश देते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं का पाठ भी किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव और राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद निषाद, समाजवादी पार्टी केरल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ साजी पोथेन थामस, नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी, विधायक आशु मलिक, रविदास मेहरोत्रा, एमएलसी जासमीर अंसारी आदि थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी अपने संपर्कों के साथ डीआईवाई (डू इट योरसेल्फ) किट साझा कर

रहे थे और अपनी आतंकी योजनाओं और डिजाइनों के वित्तपोषण के लिए धन जुटा रहे थे। इसके मुताबिक, उन्होंने युवाओं की भर्ती की और उन्हें आईईडी और हथियारों (छोटे हथियारों) के निर्माण में प्रशिक्षित किया, जिसके लिए उन्होंने आपस में डीआईवाई किट सहित प्रासंगिक सामग्री साझा की। उन्होंने कहा कि एक सैनिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी अद्वितीय होती है क्योंकि वह हर दिन मौत का सामना करता है और जानता है कि दुश्मन की गोली कभी भी, कहीं से भी आ सकती है। यह जानते हुए भी वे पूरे दिल और आत्मा से सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सैनिकों के मन में इस देश और देश के लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रेम की भावना है। उनके भीतर भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना है। समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से अपने सैनिकों के ऋणी हैं।

ट्रक-बस के पहिए थमने से प्रभावित हुई जरूरी चीजों की सप्लाई, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार ले एक्शन



रन एंड हिट मामले में संशोधित कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मल्लिम तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सरकार की तरफ से बताया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को हड़ताल समाप्त करवाने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता अखिलेश त्रिपाठी और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हिट एंड रन के प्रकरणों में लागू किए गए नए कानून के विरोध में ट्रक-बस ड्राइवर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की। चालक की हड़ताल से बस, ट्रक व टैंकरों का संचालक बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों तक आवश्यक वस्तु नहीं पहुंची है। हड़ताल के कारण सब्जी, पेट्रोल, दूध सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बाधित हो रही है। हड़ताल से आम नागरिकों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार की तरफ उपस्थित हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मामला होने के कारण सरकार संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेगी। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और आवश्यक वस्तु की सप्लाई प्रभावित न हो। हड़ताल के कारण किसी प्रकार से लां एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े।

यूपी रोडवेज की 6958 बसों में 3812 मंगलवार को नहीं चलीं, लाखों की संख्या में यात्री परेशान

मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन कानून से जुड़े बदलाव के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस चालकों की हड़ताल के चलते मंगलवार को रोडवेज बसों के चक्के लगभग जाम रहे। प्रदेश में 6958 बसों में से 3812 बसों का संचालन नहीं हो सका, इसमें से भी 2732 बसें केवल चालक नहीं मिलने के कारण बंद रही। करीब 55 फीसदी बसों का संचालन बंद रहने

से लाखों की संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 6958 बसों का संचालन प्रस्तावित था। इसमें से 3146 बसों का संचालन हुआ जबकि 3812 बसें नहीं चलीं। निगम के अधिकारी ने बताया कि बस चालकों की हड़ताल के कारण 2732, परिचालक नहीं मिलने से 7, वर्कशाप के कारण 26, यात्री नहीं

मिलने के कारण 5, अन्य कारणों से 1038 बसों का संचालन नहीं हुआ। नोएडा में सर्वाधिक 76 प्रतिशत, गाजियाबाद में 70 प्रतिशत, इटावा में 69 प्रतिशत, अयोध्या में 66 प्रतिशत, आगरा में 62 प्रतिशत, प्रयागराज में 61 प्रतिशत और चित्रकूट में 57 प्रतिशत बसों का संचालन नहीं हुआ। निजी बसों के साथ रोडवेज बसें नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी का

सामना करना पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। रोडवेज की ओर से जितनी बसें संचालित की गईं उनमें अधिकांश में क्षमता से डेढ़ गुना तक यात्रियों ने सफर किया। बस स्टैंड पर ही बसों के लिए धक्का मुक्की और भीड़भाड़ की स्थिति रही। निगम के लखनऊ रीजन की 693 बसों में से मात्र 259 ही मंगलवार को रूट पर भेजी जा सकीं।



सम्पादकीय

जीरो टॉलरेंस पॉलिसी

केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठन तहरीके हुर्रियत को UAPA के तहत पांच साल के लिए बैन कर दिया। सरकार का ये फैसला जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठन तहरीके हुर्रियत को UAPA के तहत पांच साल के लिए बैन कर दिया। कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अलीशाह गिलानी द्वारा स्थापित इस संगठन की अगुआई 2021 में उनकी मौत के बाद मसरत आलम भट के हाथों में आ गई थी, जो आजकल जेल में है।

गंभीर आरोप : केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह संगठन न केवल कश्मीर में पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करवाने और लोगों को भड़काने की कोशिशों में लगा रहता था बल्कि जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करके वहां इस्लामी शासन स्थापित करने की साजिश में भी शामिल था। यह इसके लिए पाकिस्तान से फंड जुटाने में लगा था। इसमें दो राय नहीं कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं। कोई भी जिम्मेदार सरकार इन आरोपों को हलके में नहीं ले सकती। पिछले सप्ताह ही बुधवार को सरकार, भट की अगुआई वाली पार्टी मुस्लिम लीग, जम्मू-कश्मीर को भी बैन कर चुकी है। जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी : केंद्रीय गृह मंत्री ने इस कार्रवाई को मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से जोड़ते हुए कहा है कि आगे भी अगर कोई संगठन या व्यक्ति भारत विरोधी कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत रोका जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की सख्ती की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

इकलौती कार्रवाई नहीं: यह इस तरह की कार्रवाई का कोई पहला या अलग-थलग उदाहरण नहीं है। तहरीके हुर्रियत 17वां संगठन है जिसे UAPA के तहत बैन किया गया है। बैन किए गए अन्य संगठनों में सिक्स फॉर जस्टिस (SFJ), पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), जमात-ए-इस्लामी और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) शामिल हैं। यही नहीं ऐसे संगठनों के अलावा अब तक 55 व्यक्ति (इंडिविजुअल के तौर पर) UAPA के तहत आतंकवादी करार दिए जा चुके हैं।

क्या है संदेश : सरकार की अब तक की कार्रवाई और उसके रुख से स्पष्ट है कि इस मामले में वह किसी तरह दुविधा, उलझन या संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री की बातों से यह भी संकेत मिलता है कि आगे कुछ और संगठनों के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

सावधानी भी जरूरी : देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटना वक्त की जरूरत है। इस तरह की असामान्य चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसी बिंदु पर यह कहना भी जरूरी हो जाता है कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असाधारण सतर्कता भी बरती जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे तत्वों की साजिशों का खामियाजा किसी भी रूप में देश के आम और निर्दोष नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में न भुगतना पड़े।

इस रात का अंधेरा छंटने में वक्त लगेगा, यूक्रेन और गाजा 'पावर प्ले' के ऐसे हिस्से बन गए हैं

2024 में क्या हम उन युद्धों का पटाक्षेप होते देख पा रहे हैं, जो कुछ महीने या कुछ वर्ष पहले शुरू हुए थे। आज की दुनिया पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के बीच बनी गहरी खाइयों से बाहर आती नहीं दिख रही। ये खाइयां अगर और गहरी हुईं तो संघर्षों की आशंकाएं और उनकी तीव्रताएं और बढ़ जाएंगी। हालांकि ये परिदृश्य नए नहीं हैं बल्कि समूचा इतिहास इनसे भरा हुआ है। इसलिए परिणाम से पहले इनके पीछे के कारणों को जानने की ज्यादा जरूरत होगी। सच जाने बिना इस निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल है कि रूस-यूक्रेन और इस्राइल-गाजा युद्ध कितनी दूर तक जाएंगे।

पहले यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। 24 फरवरी 2022 की सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दोनबास इलाके में 'सैन्य कार्रवाई' की घोषणा से ठीक पहले अपने भाषण में कहा था कि 1991 में सोवियत यूनियन बिखरा तो रूस पर डाका डाल दिया गया। पुतिन का यह बयान एक तरह से हिटलर के उस आरोप की पुनरावृत्ति था, जिसमें वर्साय की संधि को 'राजमार्ग की डकैती' कहा गया था। उस समय पुतिन सोवियत संघ की पुरानी कड़ियों को जोड़ते हुए अपने ही अंदर एक युद्ध लड़ते हुए दिख रहे थे। यदि ऐसा है तो रूस-यूक्रेन युद्ध अभी अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाया है।

प्रतिष्ठा का प्रश्न दरअसल, मॉस्को-कीव के बीच लड़ी जा रही लड़ाई का सच वह नहीं है जो दुनिया को बताया जा रहा है। यह लड़ाई सिर्फ पुतिन की

महत्वाकांक्षाओं की नहीं है बल्कि सोवियत संघ के खंडहर पर उगे स्वतंत्र देशों के बीच रूस की प्रतिष्ठा की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और नैटो 1991 के बाद से ही रूस को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पुतिन रूस को पुराने इतिहास की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। नए समीकरण

चूंकि, अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां सीधे टकराने के बजाय अक्सर मोहरों के जरिए युद्ध लड़ती रही हैं, इसलिए लड़ाई कहीं और हो रही है, मगर दिख कहीं और रही है। अब इस लड़ाई का स्वरूप बदल चुका है। अब इसे मॉस्को-पेइचिंग बॉन्डिंग या इससे भी आगे मॉस्को-पेइचिंग-तेहरान-रियाद के बीच बनते समीकरणों के सापेक्ष देखा जाए।

रूस की बाजी एक बात और, नैटो शक्तियां नहीं चाहती कि कैस्पियन से ब्लैक सी तक की जियो-स्ट्रैटेजिक बेल्ट में रूस इतना मजबूत हो जाए कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस उसकी तरफ शिफ्ट कर जाए। लेकिन पश्चिमी शक्तियां कुछ खास कर पातीं, इससे पहले ही रूस ने ब्राइमिया पर कब्जा (वर्ष 2014) कर संतुलन अपने पक्ष में कर लिया।

यह रूस की रणनीतिक विजय थी और पश्चिमी दुनिया की पराजय। लीडरशिप की लड़ाई इसे स्वीकार कर पाना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए कहीं से युद्ध शुरू होने की जरूरत थी। इस युद्ध की शुरुआत हुई यूक्रेन से। गौर से देखें तो अभी यूरेशियाई क्षेत्र में नियंत्रण और लीडरशिप को लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है, इसलिए अभी

लड़ाई थमने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मरती संवेदनाएं

इस्राइल-गाजा संघर्ष भी इसी तरह के इतिहास का एक अध्याय है, जिसे दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ही लिखना शुरू कर दिया गया था। ताजा संघर्ष में गाजा में अब तक 20 हजार मौतें हुई हैं, 54 हजार से अधिक घायल हैं। मारे गए अधिकतर लोगों में महिलाएं और बच्चे हैं। यह महिलाओं और बच्चों की नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की मौत है, जिसे न ही मध्य-पूर्व के क्रूर शासक समझ पाएंगे और न ही इस्राइल के चुने हुए नेता। फिर हमास के चरमपंथियों (आतंकवादियों) से तो कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती। जब तक इन संवेदनाओं का मर्म समझ में नहीं आएगा, तब तक युद्ध कैसे रुक सकते हैं?

लक्ष्य क्या है बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यह कह रहे हैं कि गाजा में जारी अंधाधुंध बमबारी के कारण इस्राइल वैश्विक समर्थन खो रहा है। इस्राइली सेना भी मान रही है कि यह अभियान 'मुश्किल' और 'लंबा' होगा।

लेकिन इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को तब तक जारी रखना चाहते हैं, जब तक वे अपने सभी लक्ष्य हासिल न कर लें। ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ गाजा है या येरुशलम? अगर येरुशलम है तो अभी और कीमतें चुकानी पड़ेंगी? संकट के जिम्मेदार वैसे नेतन्याहू यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि इस युद्ध के लिए इस्राइल 'बहुत भारी कीमत' चुका रहा है, लेकिन इसके साथ यह भी कह रहे हैं कि

'लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।' तो उस क्षेत्र में ऐसा है कौन जो युद्ध नहीं चाहता? इस्राइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान या मध्य-पूर्व के वे देश या संगठन जो मध्य-पूर्व राजनीति पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी खासा प्रभाव रखते हैं? या फिर अमेरिका सहित पश्चिमी दुनिया के वे देश, जो इस मध्य-पूर्व के इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं।

लंबी खिंचेगी लड़ाई हालांकि इजिप्ट की तरफ से युद्धविराम की एक नई त्रिस्तरीय योजना पेश की गई थी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं दिख रहा है जैसे कि इस योजना में था। इसमें दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई के अलावा मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाने की योजना और एक विस्तृत युद्धविराम जैसे विषय हैं, जो जमीन पर नहीं दिख रहे हैं।

कारण यह कि इस्राइल को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसमें उत्तरी गाजा ही नहीं दक्षिणी गाजा और येरुशलम भी शामिल है। शांति से दूर यूक्रेन और गाजा 'पावर प्ले' के ऐसे हिस्से बन गए हैं, जिन्हें दुनिया की ताकतें 'क्लिक एंड ब्राउज' पैटर्न पर चलाती हुईं दिख रही हैं। शेष दुनिया भी इसे देखकर हैरान नहीं है, भले ही इन ताकतों के साथ न खड़ी हो।

फिलहाल दुनिया फिर से ग्रेड डिवाइड्स से गुजरती हुईं दिख रही है जिसमें आमतौर पर नए किस्म के टकराव होते हैं। ऐसे में यही लगता है कि 2024 युद्धविराम से अभी दूर ही खड़ा है।

नशा एक अभिशाप है

आज की भागमभाग भरी जिंदगी में मानवीय संवेदनाओं का हास हुआ है। जिसकी वजह से आपसी सौहार्द कम हुआ है, सतही और खोखले रिश्तों के कारण आपसी विश्वास में कमी आयी है। संयुक्त परिवारों में कमी, बाजारवाद और पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव और नैतिक शिक्षा में कमी की वजह से बच्चे, जवान, बूढ़े आसानी से पथ विचलित हो जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई बुरी आदतें अपना प्रभाव इन बुराईयों में से एक हैं जो कि हर आयुवर्ग के लोगों को अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी), एम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दसक में भारत में नशा करने वालों की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ गई है और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में सोलह करोड़ लोग शराबी हैं और हर साल नशे से करीब साढ़े सात हजार लोग

मौत के मुँह में समा जाते हैं। इस नशे के खिलाफ बृहद जनजागरण अभियान की नितांत आवश्यकता है। हमारे चारों ओर ऐसी ही कई घटनाएं घटित होती हैं जो कि नशे की ओर आसानी से खींच लेती हैं। शायद मुझ जैसे कई साथियों में जागरूकता रही होगी जिसके कारण नशे से बचे रहे। मैं जब कक्षा दस में पढता था तो हमारे इलाके का माहौल बहुत ज्यादा मोटिवेशनल नहीं था, इलाके में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बच्चों को अच्छी सीख दे सके। हम 10-12 लोग रोज पैदल ही 6-7 किलोमीटर दूर इण्टर कॉलेज में पढ़ने जाते थे। हमारे कई साथी रोज 8 बजे घर से निकलकर पास के जंगल में दिनभर छिप जाते थे और शाम को 3-4 बजे घर आ जाते थे। शायद उन्हें ऐसा करने में मजा आता होगा। इनमे से कई छात्र भांग के पेड़ों से चरस निकालकर बीड़ी में भरकर उसका सुट्टा लगाकर मस्त हो जाते थे। दिनभर आनंदमय रहने का विचारकर

और धूप सेंक कर शाम को घर आ जाते थे? आखिर वे सभी ऐसा क्यों करते होंगे? वे बच्चे कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते होंगे क्या? इनमे से कई तो हाई स्कूल भी नहीं कर पाए। क्या यह उस स्कूल की भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उन बच्चों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करता, जो महीनों विद्यालय से गायब रहते थे? यह हाल उस दौर में ज्यादातर विद्यालयों का था। उन दिनों हाई स्कूल और इण्टर का रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 20-30 प्रतिशत तक ही रहता था। आज जब सोचता हूँ कि यह डिवाइन डेस्टिनी ही होगी कि मैं और मेरे एकाध साथी उस माहौल में नशे से कैसे बच गए होंगे। अन्य साथियों को ऐसी कुबुद्धि क्यों आयी होगी? काश कोई प्रभावशाली व्यक्ति इन सभीको मोटीवेट कर पाता तो शायद वे भी नशे की तरफ नहीं जाते। यह नशा व्यक्ति विशेष के साथ परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है। आने वाली पीढ़ियां

भी नशे के कारण बर्बाद हो जाती हैं। यह गनीमत थी कि उन दिनों गांजा और चरस का ही नशा ग्रामीण क्षेत्रों में था, यदि आज की तरह के महंगे नशे होते तो न जाने समाज की दशा क्या होती? आज तो हर स्कूल, जिम और खेल मैदान के आस पास नशा करने और करवाने वाले एजेंट मिल ही जायेंगे जो कि नए नए बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रबंध करते हैं। यह हाल पूरे भारतवर्ष में है और बच्चे नशे की गिरफ्त में आसानी से आ जा रहे हैं। हमें ठोस कदम उठाते हुवे अपने बच्चों को नशे से बचाना होगा।

लत यानी एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है जैसे हम जैसे लोग काफी चाय पीते हैं, कई बच्चे विडिओ गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, आजकल कई एडल्ट भी तो घंटों फेसबुक या यूट्यूब वीडियो देखते हैं, यह सभी चीजें लत कहलाती हैं। इन सभी लतों से आदमी की सृजनात्मकता का हास होता है।

भिंवंडी में नए वर्ष के शुभारंभ पर 182 पियकड़ों पर हुई कार्यवाई, वसूला 56 हजार दंड

सिटी न्यूज मुंबई/गनी खान

भिंवंडी में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जमकर धरपकड़ की। 31 दिसंबर की रात पुलिस ने 182 बेवडों पर केस दर्ज किया है। साथ ही इस दौरान 56 हजार 500 रुपए बतौर दंड भी वसूल किया है। साथ ही नियम कानून को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले कई दर्जन वाहन चालकों पर भी केस दर्ज किया। भिवंडी के तीनों यातायात विभाग पुलिस द्वारा 31 दिसंबर की रात जोरदार पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। इस दौरान नियम कानून को ताक पर रखकर व शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 182 वाहन चालकों पर कार्यवाई की गई। जबकि नियम कानून को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर केस दर्ज किया गया लेकिन सबसे ज्यादा कार्यवाई



भिंवंडी शहर यातायात पुलिस द्वारा की गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष पाटील ने बताया कि भिवंडी शहर यातायात विभाग ने दारू पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 17 लोगों के विरोध में वाहतूक कायदा कलम 185 के तहत दारू पीकर गाड़ी चलाने तथा चालक के पीछे बैठे दोनों लोगों के विरोध में कालम 188 के तहत केस

दर्ज किया है। वहीं 79 वाहन चालकों पर 56 हजार 500 रुपये की दंडात्मक कारवाई की गई है। इसी तरह कोनगाव यातायात पुलिस ने कालम 185 के तहत 16 तथा कालम 188 के तहत 11 सहित कुल 27 लोगों के विरोध कार्यवाई किया है। जबकि नारपोली यातायात पुलिस ने 57 दारू पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के

खिलाफ केस दर्ज किया है।

पहले ही दी गई थी पुलिस द्वारा नसीहत

ठाणे यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर भिवंडी की सभी मुख्य नाकों व चौराहों पर 31 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के साथ साथ बेवडों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जोरदार नाकाबंदी लगाई थी। क्योंकि भिवंडी के डीसीपी नवनाथ ढवले व यातायात पुलिस विभाग के डीसीपी ने 31 दिसंबर की रात में नए वर्ष की स्वागत शांतिपूर्वक मनाने की अपील पहले ही किया था। साथ ही उन्होंने दारू पीकर गाड़ी न चलाने के साथ वाहनों द्वारा रेंसिंग न करने की नसीहत दिया था और नियम कानून तोड़ने वालों पर कार्यवाई करने की भी बात की गई थी।

पानी का पाइप डालने के लिए बिना परमिशन सड़क की अवैध तरीके से की खुदाई

सिटी न्यूज मुंबई/गनी खान भिवंडी के नारपोली इलाके में पानी का पाइप लाइन डालने के लिए बिना परमिशन अवैध तरीके से सड़क की खुदाई कर मनपा को एक लाख 10 हजार का आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में मनपा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने एक डाइंग मालिक सहित दो पर केस दर्ज किया है। मनपा प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही पानी चोरों पर कार्यवाई से हड़कंप मच गया है।

पुलिस के अनुसार भिवंडी के नारपोली इलाके में शंकर डाइंग नामक प्रोसेस हाउस स्थित है। जिसके मालिक राहुल केडिया व मैनेजर भवानी चौधरी ने आपस में मिलीभगत कर बिना मनपा प्रशासन से किसी प्रकार का परमिशन लिए अवैध तरीके 7 नवंबर को मनपा के डामरीकरण किए गए सार्वजनिक रोड को डाइंग में पानी सप्लाई हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की। इस कारण गटर व नाले का दुर्गन्धयुक्त पानी रास्ते पर बहने लगा। जिसके कारण जनता की स्वास्थ्य खराब होने के साथ सुगंध के कारण बिमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। इतना ही डाइंग मालिक के उक्त कृत्य के कारण मनपा प्रशासन को 1 लाख 9 हजार 885 रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ। इस प्रकरण में मनपा पथक प्रमुख विराज मनोहर भोईर ने एक जनवरी को नारपोली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 432 सहित विभिन्न धाराओं के तहत डाइंग मालिक व मैनेजर पर केस दर्ज कराया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक के.आर.पाटील कर रहे हैं। इससे पहले कई डाइंग, सायजिंग व बिल्डिंगों पर मनपा प्रशासन द्वारा पानी चोरी का केस दर्ज कराया गया है।

बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, ट्रैफिक जाम



मुंबई: केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम का देशभर के बस-ट्रक चालकों ने कड़ा विरोध किया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने बंद बुलाया है। इसका परिणाम कई क्षेत्रों में दिख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालक **शेष पृष्ठ 7 पर**

मनपा की छापेमारी कारवाई, 755 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त, 20 हजार रुपये दंड वसूल

सिटी न्यूज मुंबई/गनी खान भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जिसे लेकर शहर में स्वच्छता अभियान, शहर की सफाई के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण एवं कार्यवाही की जा रही है। इस तरह मंगलवार के दिन मनपा की तरफ से प्रभाग समिती नंबर 5 के महावीर इंटरप्राइजेज, मेट्रो ट्रेडर्स दो व्यापारियों की दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग करने के मामले में छापामारकर कुल 755 किलोग्राम प्लास्टिक जप्त किया गया।



प्लास्टिक जब्ती कर और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल करते हुए कुल 20 हजार रुपए वसूल किए गए। साथ ही पान टपरी पर

कारवाई में सहायक आयुक्त फैसल ततली, वार्ड स्वास्थ्य निरीक्षक शशिकांत घाडगे, स्वास्थ्य निरीक्षक उत्तम जाधव, रूपेश गायकवाड़ और सुमित कांबले, अभिराज भालेराव सहित सभी मुकादम शामिल रहे। मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि व्यापारी, दुकानदार, फेरीवाले के साथ-साथ नागरिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, यदि इस तरह की हरकत में कोई पकड़ा गया तो पहले तीन बार दंडात्मक कारवाई की जाएगी और फिर कानूनी कारवाई की जाएगी।

राज्य भर में ईंधन की आपूर्ति बंद, मुंबई में 210 पेट्रोल पंप रात तक बंद रहेंगे?

मुंबई: केंद्र सरकार (central government) के खिलाफ ट्रक-टैंकर ड्राइवरों (truck-tanker drivers) द्वारा बुलाई गई हड़ताल का (strike called) असर अब पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। इससे राज्य में ईंधन आपूर्ति बाधित हो गयी है। इसका नतीजा मुंबई में भी देखने को मिला है। बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) क्षेत्र के 210 पंपों में से आधे बंद होने लगे हैं। पेट्रोल पंप

ओनर्स एसोसिएशन (Owners Association) ने जानकारी दी है कि अगर रात तक सप्लाई शुरू नहीं हुई तो सभी पंप बंद कर दिये जायेंगे। 12 जिलों में ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई। सोमवार को तीनों कंपनियों का एक भी टैंकर ईंधन लेकर नहीं जा सका, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पारित नए सड़क दुर्घटना सुरक्षा अधिनियम (Road Accident Safety Act) को दमनकारी और अनुचित बताते हुए



मनमा के पास नागापुर इलाके के पनवाड़ी में तेल कंपनियों के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के कारण मनमाड इलाके के तेल संयंत्र से राज्य के 12 जिलों को ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे ईंधन की कमी का संकट पैदा हो गया है। टैंकर चालकों का कहना है कि केंद्र के नए कानून के मुताबिक, अगर ईंधन टैंकर या ट्रक से कोई दुर्घटना होती है और चालक दुर्घटनास्थल से भाग जाता है, तो चालक को 10 साल की

कैद और बिना जमानत के 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। टैंकर चालकों ने इसका कड़ा विरोध जताया है और इस कानून को वापस लेने के लिए टैंकर चालकों ने सोमवार सुबह हथियार उठा लिया। टैंकर मालिकों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके चलते राज्य के बारह जिलों में तीन कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पनवाड़ी, नागापुर **शेष पृष्ठ 7 पर**

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राइजेस धरती कॉम्प्लेक्स शॉप नं. 11, एवरशाइन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्यालय- धरती कॉम्प्लेक्स शॉप नं. 11, एवरशाइन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र। मुंबई कार्यालय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483

Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486